

-2-

सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत योजना

देश में औसत आयु बढ़ने के साथ-साथ सेवा निवृत्त व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त हो जाता है और औसतन 70 वर्ष तक सक्रिय रहता है। न्यूक्लियर व सीमित परिवार होने के कारण व्यक्ति को अकेले ही रहना पड़ता है और वे जीवन में एक रिक्तता का अनुभव करते हैं। उनके पास अनुभव का असीम भंडार होता है किन्तु उसका कोई उपयोग समाज में नहीं हो पा रहा है। समाज से जो सम्मान व समृद्धि प्राप्त की है वह उसे किसी न किसी रूप में वापस भी करना चाहता है।

वृद्धावस्था में बीमारियों के अतिरिक्त जीवन में अवसाद भी बढ़ जाता है। देश की इतनी बड़ी जनसंख्या यदि इसी वातावरण में रही तो यह देश के विकास के लिए घातक होगा। राज्य प्राधिकरण ऐसे व्यक्तियों के अनुभवों का समाज में उपयोग करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों को लोक अदालत की विभिन्न योजनाओं में नियुक्त कर उनका लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन समाज मात्र न्यायिक अधिकारियों से ही नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, चिकित्सा व अभियांत्रिकी अधिकारी/कर्मचारी भी सेवा निवृत्ति के उपरान्त समाज के विकास में योगदान करना चाहते हैं। आवश्यकता है उनको सम्मान सहित अवसर देने की। जहाँ बड़े बड़े शहरों में वरिष्ठ श्रेणी के सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी मिल जायेंगे वहीं छोटे छोटे शहरों, कस्बों एवं गांवों में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता होगी।

यदि प्रत्येक पुलिस थाना/पुलिस चौकी के क्षेत्र में रहने वाले सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची बनाकर उसमें से उपयुक्त, इच्छुक व्यक्तियों का चयन कर उनकी सहायता छोटे छोटे मामलों जैसे मार-पीट, नाले परनाले एवं मेड बंदी आदि के विवादों को सुलझाने में ली जाये, तो न केवल न्यायालय में आने वाले मुकदमों में कमी होगी अपितु समाज में सदभावना भी बढ़ेगी और समाज में पुलिस की स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। बस इतना ही सुनिश्चित करना है कि चयन मात्र इच्छुक व उपयुक्त व्यक्तियों का ही किया जाये। यदि इस विचार पर सहमति बनती है तो उसे व्यवहार में भी लाया जा सकता है। जैसे ही कोई विवाद पुलिस थाने में जाता है तो उसे उक्त चयनित व्यक्तियों में से दो-तीन सदस्यों के पैनल को संदर्भित कर दिया जाये जो स्थल पर जाकर विवाद को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को विधिक मान्यता देने के लिए प्राधिकरण काउन्सलर के रूप में उन्हें नियुक्त कर सकता है। पुलिस से मात्र इतनी ही अपेक्षा होगी कि वह ऐसे काउन्सलर्स को सम्मान देते हुए उनका सहयोग लेने का प्रयास करे। काउन्सलर के चयन का अधिकार संबंधित जिला जज या सिविल जज को दिया जा सकता है। प्रारम्भ में ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाये जो सेवा भाव रखकर इस कार्य के लिए इच्छुक हों। बाद में उनको मार्ग व्यय दिये जाने की व्यवस्था करने के लिए विचार किया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि अधिकांश विवादों को पक्षकारों को एक साथ बैठाकर वहीं सुलझाया जा सकता

यु.के.
सचिव-2
उप-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
लखनऊ

है। न्यायालय में आने से वैमनयस्ता में वृद्धि हो जाती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य प्राधिकरण में प्री-लिटीगेशन योजना प्रभावी है किन्तु उससे छोटे छोटे मामलों/झगड़ों को निपटाने में प्रभावी सहायता नहीं मिल पा रही है। तहसील दिवस, थाना दिवस पर भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवादों के प्रभावी शमन की सम्भावना नहीं रहती है जब पक्षकारों के बीच के ही लोग रहेंगे जो किसी न किसी रूप में सरकारी सेवक भी रहे हैं तो उनकी विश्वसनीयता और स्वीकार्यता तुलनात्मक रूप से अधिक होगी।

इस प्रकार के काउन्सलर्स को विभिन्न मजिस्ट्रेट न्यायालय से संबद्ध कर पक्षकारों के बीच सुलह समझौते का प्रयास किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा स्थापित सुलह समझौता केन्द्र में मात्र पारिवारिक विवादों पर ही विचार किया जा रहा है। मकान मालिक, किरायेदार, पारिवारिक सम्पत्ति एवं ऐसे अन्य विवादों को ऐसे काउन्सलर द्वारा सुलझाया जा सकता है सुविधानुसार उनके बैठने का समय सांयकाल 4.00 बजे नियत किया जा सकता है। इसके लिए न्यायालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को मानदेय पर नियुक्त किया जा सकता है ताकि न्यायालय की प्रक्रिया आदि का पालन भी सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार एक ही परिसर में छोट छोट मामलों में सुलह समझौते का प्रयास किया जा सकता है। न्यायालयों में लीगल एड क्लीनिक कार्यरत हैं। प्रदेश के 11 जनपदों में मीडियेशन सेन्टर भी कार्यरत हैं। प्रत्येक जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय भी है। इस पृष्ठ भूमि में विस्तृत एवं समयक विचारोपरान्त इस योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है। हो सकता है कि प्रारम्भ में अच्छे परिणाम न मिले लेकिन प्रयासों के बाद प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं।

A handwritten signature in blue ink is positioned above a circular official stamp. The stamp contains text in Hindi, including the name of the organization and the name of the official, though the text is partially obscured and difficult to read.